DUTA-DUCKU-DUSU

In Defence of Public-funded Higher Education

Teachers, students and karmacharis have come together to protest against the anti-education policies of the Government. Ignoring the consistent demand for allocating at least 6% of the GDP on Education, successive Governments have neglected and starved universities of infrastructure and permanent appointments. Teachers have been denied promotions and pensions and contractualisation of non-teaching employees has become the norm. This year, the Union Budget allocation to Education has been reduced to less than 1% of the Gross National Income. Its share in the Budget spending has come down to 3.48%. The recent Government demand that the universities raise resources to meet at least 30% of the additional expenditure due to pay revision will increase the cost of education and make it inaccessible to most.

- **30:70 Funding Formula**: Universities are now being asked to generate at least 30% of the additional costs towards revised salaries for teachers and non-teaching staff. This money will be drawn out of student fees. This means that average expenditure in fees of Rs. 50,000 for a 3 yr UG degree will go up to several lakhs! This new funding formula, if implemented, will make higher education inaccessible to most students, especially women students.
- **Loans in place of Grants**: The Government is asking all universities, including IITs and IIMs, to take loans from the Higher Education Funding Agency (HEFA), instead of giving grants as it used to, for any additional infrastructure. While the budget allocation to the UGC has come down, the HEFA has been given a huge allocation. Universities are being forced sign MOU's for this new business model under which they will have to demonstrate a capacity for resource generation and repayment of the loan over a fixed period of time. This will lead to commercialisation and place an unbearable financial burden on students.
- **Autonomous Colleges Scheme**: The Government's move to grant 'autonomy' to colleges of repute is a ploy to impose 'financial autonomy' on them and thereby convert them into teaching shops. These colleges will be compelled to increase fees and generate their own resources by introducing self-financing courses. Managements will be much less accountable to University rules and regulations and more likely to bypass democratic norms.

Join People's March from Mandi House to Parliament Street

28 March 2018, 12.30 pm

- **Graded Autonomy**: Universities will be classified into different categories on the basis of their rating/ranking under NAAC/NIRF, and pushed into different levels of self-financing and commercialisation.
- **No jobs**: DU is already facing a huge crisis as 60% of its faculty are working on ad-hoc and guest basis. Non-teaching posts have already been contractualised. Instead of filling up vacant posts as demanded by teachers, reduction of posts and contractual appointments are being proposed by the Government. This will drive out talent from the teaching profession, adversely affecting the quality of education.
- **No Promotions**: Teachers have been denied promotions for many years because of an irrational promotion policy that imposed a bureaucratic and unacademic quantification of teachers' work. There is widespread demoralisation amongst teachers which has already resulted in experienced teachers leaving public-funded educational institutions for private universities.
- **VII Pay Revision**: The latest MHRD notification on pay revision has refused to honour the principle of parity of teachers with All India Services, thereby diverting talented students away from choosing teaching as a career.

All these developments spell disaster for public-funded Higher Education. Eventually, students from middle-class and economically marginalised families, especially female students, will be excluded from Higher Education. Students, karmacharis and teachers need to unitedly fight to defend our rights. It's now or never! Join the movement, participate in the forthcoming joint action-programmes.

---------Appeal Issued By DUTA

सार्वजनिक वित्तपोषण वाली उच्च शिक्षा की हिफ़ाज़त में

डूटा-डूसू-डूकू

यह ऐतिहासिक अवसर है जब सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों की मुखालफ़त के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी एक साथ आये हैं. शिक्षा के लिए जीडीपी का कम-से-कम 6 फ़ीसद आवंटित करने की हमेशा की मांग को अनदेखा करते हुए एक के बाद एक सरकारें विश्वविद्यालयों की घोर उपेक्षा करती आयी हैं, इन्हें आधारभूत संरचना और स्थायी नियुक्तियों का मोहताज बना दिया गया है. शिक्षकों को पदोन्नति और पेंशन से वंचित किया जाता रहा है और शिक्षकेतर कर्मचारियों का ठेकाकरण एक सामान्य बात हो गयी है. इस साल के केन्द्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटन सकल राष्ट्रीय आय के 1 फ़ीसद से भी कम है. बजट व्यय में शिक्षा का हिस्सा घटकर 3.48 फ़ीसद रह गया है. विश्वविद्यालयों को अपनी बढ़ी हुई वित्तीय ज़रूरतों का कम-से-कम 30 फ़ीसद खुद उगाहने के लिए मजबूर करने वाली हालिया घोषणा शिक्षा को और महंगा करेगी और इसे ज़्यादातर लोगों की पहुंच से दूर कर देगी.

- **30:70 फंडिंग फ़ॉर्मूला:** विश्वविद्यालयों को कहा जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के कारण बढ़े हुए वित्तीय भार का 30% वे खुद उगाहें. यह पैसा विद्यार्थियों की फीस से निकाला जाएगा. इसका मतलब यह कि 3 साल की स्नातक डिग्री के लिए अभी फीस के रूप में जो औसत खर्च 50,000 के लगभग है, वह कई लाख में पहुंच जाएगा! यह नया फंडिंग फ़ॉर्मूला अगर लागू हुआ तो उच्च शिक्षा अधिकांश विद्यार्थियों, खासकर महिला विद्यार्थियों की पहुंच से दूर हो जायेगी.
- **ग्रांट की जगह लोन:** सरकार आईआईटी और आईआईएॅम समेत तमाम विश्वविद्यालयों को किसी भी अतिरिक्त आधारभूत संरचना के लिए पहले की तरह ग्रांट देने के बजाये उन्हें हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी (हेफा) से लोन लेने के लिए कह रही है. जहां यूजीसी के लिए बजट आवंटन कम हो गया है वहीं हेफा को बहुत बड़ा आवंटन मिला है. विश्वविद्यालयों को इस नए बिज़नेस मॉडल के लिए एमओयू साइन करने को बाध्य किया जा रहा है जिसके तहत उन्हें अपने संसाधन पैदा करने और निर्धारित समय के भीतर लोन चुकता करने की क्षमता प्रदर्शित करनी है. इस तरह शिक्षा का व्यावसायीकरण होना है जिससे विद्यार्थियों पर खर्चे का भयंकर बोझ आना तय है.
- **स्वायत्त कॉलेज की योजना:** प्रतिष्ठित कॉलेजों को 'स्वायत्तता' देने का सरकारी क़दम उन पर 'वित्तीय स्वायत्तता' थोपने और इस तरह उन्हें शिक्षा की दुकानों में तब्दील करने की साज़िश है. ये कॉलेज अपनी फीस बढ़ाने और सेल्फ-फाइनेंसिंग पाठ्यक्रम लागू कर अपने संसाधन पैदा करने के लिए बाध्य होंगे. इनके प्रबंधन में विश्वविद्यालय के नियमों के प्रति लापरवाही होगी और लोकतांत्रिक उसूलों की अनदेखी करने का रुझान उनमें ज़्यादा होगा.
- **ग्रेडेड ऑटोनोमी:** एनएएसी(नाक)/एनआईआरएफ के तहत मिली रेटिंग/रैंकिंग के आधार पर विश्वविद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा और उन्हें धकिया कर व्यावसायीकरण तथा सेल्फ-फाइनेंसिंग के अलग-अलग स्तरों पहुंचाया जाएगा.
- **नौकरियां नदारद:** डीयू पहले से ही एक संकट से गुज़र रहा है. इसके 60% शिक्षक तदर्थ और अतिथि की हैसियत में हैं. शिक्षकेतर पदों का ठेकाकरण किया जा चुका है. शिक्षकों की मांग के अनुरूप खाली जगहों को भरने के बजाये सरकार पदों में कमी लाने और ठेके पर नियुक्तियां करने का प्रस्ताव ला रही है. ज़ाहिर है, इससे प्रतिभाएं शिक्षण के पेशे से विमुख होंगी और शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा.
- **पदोन्नति नदारद:** शिक्षक के काम पर नौकरशाहाना और ग़ैर-अकादमिक शर्तें थोपने वाली अतार्किक पदोन्नति योजना के कारण कई सालों से शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिली है. शिक्षकों का मनोबल बुरी तरह टूटा हुआ है और पब्लिक-फंडेड संस्थाएं छोड़कर निजी संस्थाओं में अनुभवी शिक्षकों के जाने के रूप में इसके नतीजे दिखने लगे हैं.
- **सातवां वेतन आयोग:** वेतन संशोधन पर एमएचआरडी की ताज़ा अधिसूचना में अखिल भारतीय सेवाओं के साथ शिक्षकों की बराबरी के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है. यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षक के पेशे में आने से और हतोत्साह करेगा.

ये सारे कारगुज़ारियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कहर बरपा करने जा रही हैं. इनके नतीजे के तौर पर मध्यवर्ग और गरीब तबके से आनेवाले विद्यार्थी, ख़ासकर महिला विद्यार्थी, उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर हो जायेंगे. विद्यार्थी, कर्मचारी और शिक्षक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ें, यह समय की मांग है. हमें समझना होगा–अगर अभी नहीं, तो कभी नहीं!